

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा फरवरी, 2017 माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

1. केंद्र सरकार में अखिल भारतीय सेवा के अधिकांश कारियों की कमी को दूर करने के लिए ए.दि.नांक 03.02.2017 को राज्यमंत्री (कार्मिक) की ओर से 19 राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को एक अर्द्ध सरकारी पत्र भेजा गया, जिसमें तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में राज्यवार कमी दर्शाई गई थी तथा उनसे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकांश कारियों को छोड़ने का अनुरोध किया गया था।
2. विभिन्न सेवाओं/पदों की रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2017 में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा – सिविल सेवा परीक्षा के लिए नियम, दि.नांक 22 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. 13018/1/2017 – एआईएस (I) द्वारा सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किए गए थे।
3. सेवा में शामिल परिवीक्षाधीन अधिकांश कारियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षण की अवधि के दौरान खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा केंद्र अथवा राज्य सरकार में नियुक्ति के लिए सिविल सेवा परीक्षा या किसी अन्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1968 को दि.नांक 15.02.2017 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया।
4. भारतीय पुलिस सेवा – हरियाणा तथा गुजरात संवर्ग की संवर्ग समीक्षा दि.नांक 01.02.2017 को अधिसूचित की गई।
5. भारतीय वन सेवा – नागालैंड संवर्ग तथा भारतीय वन सेवा – गुजरात संवर्ग की संवर्ग समीक्षा क्रमशः दि.नांक 27.02.2017 तथा 28.02.2017 को अधिसूचित की गई।
6. एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) ए.एस. भोंसले तथा श्रीमती सुजाता मेहता को दि.नांक 22.02.2017 – स्था.(ख) के विभाग के आदेश संख्या 39019/04/2016 द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।
7. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तर की नियुक्तियों से संबंधित दिशानिर्देशों का सारांश दि.नांक 23 फरवरी, 2017 के अर्द्धसरकारी पत्र सं. 28/43(ईओ)/2013-एसीसी के माध्यम से अद्यतित कर सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को वितरित किया गया। अद्यतित सारांश को कार्मिक

और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है जिसे (<http://dopt.gov.in/notification/oms-and-orders>) लिंक पर देखा जा सकता है।

8. इस विभाग ने दिनांक 17 फरवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/6/2016-स्था (वेतन-II) द्वारा दिनांक 17 जून, 2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-(वेतन-II) के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में मंत्रालयों/विभागों/उधार पर सेवाएं लेने वाले संगठनों को प्रतिनिधित्व अवधि को एक बार में 7 वर्ष की अवधि तक के लिए प्रतिनिधित्व करने की शक्ति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, दिनांक 23 फरवरी, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/6/2016-स्था.(वेतन-II) द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि प्रतिनिधित्व 'ड्यूटी' भत्ता की देयता केवल दिनांक 17 जून, 2010 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 8.3.2 के अनुसार, अर्थात् केवल पांचवें वर्ष तक होगी, यदि प्रतिनिधित्व अधिकारी ने प्रतिनिधित्व (ड्यूटी) भत्ता लेने का विकल्प चुना है।
9. कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आधार (वितीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित विवरण) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अनुपालन में दिनांक 15/02/2017 की अधिसूचना सं. 1194940/सीडब्ल्यूओ/2016-डीबीटी सेल द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों की सूची प्रकाशित की।
10. इस विभाग के दिनांक 14 फरवरी, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 20/1/2011- निदेशक (कैंटीन) द्वारा गैर-सांविधिक विभागीय जलपानगृह के कर्मचारियों के बच्चों के लिए जलपानगृह निदेशक की विचाराधीन निधि से चलाई जाने वाली छात्रवृत्ति स्कीम को संशोधित किया गया।
11. दिनांक 9 फरवरी, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/03/2015-स्था.(प्रशा.IV) द्वारा ऐसे मामलों जहां कोई सरकारी सेवक नजदीकी एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/बस टर्मिनल तक एलटीसी पर अधिभूत परिवहन के साधन से यात्रा करता है तथा घोषित स्थान के भ्रमण की शेषयात्रा निजी परिवहन/स्व-प्रबंध (जैसे व्यक्तिगत वाहन अथवा निजी टैक्सी आदि द्वारा) करता है, के संबंध में कार्रवाई करने के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने पर अनुदेश जारी किए गए।
12. भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के सहयोग से कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा सीवीसी, सतर्कता भवन, नई दिल्ली में दिनांक 15.02.2017 को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया तथा इस शिविर में 52 कर्मचारियों ने रक्तदान किया।
13. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित अखिल भारतीय सेवा (डीसीआरबी) नियमावली, 1958 में संशोधन को दिनांक 27.02.2017 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया।
14. इस विभाग के दिनांक 10.02.2017 की अधिसूचना सं. 39019/05/96-स्था.(ख)(भाग-IV) द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों को संशोधित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) नियमावली, 1969 में संशोधन।

15. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से पैदा होने वाली विसंगतियों को दूर करने के लिए ए.दि.नांक 02.02.2017 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा विसंगतियों की स्थापना का आदेश जारी किया गया है।
16. परवर्ती राज्यों आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के मध्य राज्य संवर्ग के कर्मचारियों (भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से भिन्न) के आबंटन के लिए ए.श्री.सी.आर.कमलानाथन की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति के कार्यकाल को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 3 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2017 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सलाहकार समिति ने सभी 90 विभागाध्यक्षों के संबंध में अंतिम आबंटन की जांच तथा सिफारिश कर दी है तथा 90 विभागों के लगभग 56000 कर्मचारियों (कुछ श्रेणियों को छोड़कर जहां माननीय उच्च न्यायालय/आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण ने कर्मचारियों के संभावित/अंतिम आबंटन पर 'अंतरिम रोक' लगायी है) के संबंध में अंतिम आबंटन आदेशों को जारी कर दिया है।
17. सीसीएससीएसबी ने बैडमिंटन, टेबल टेनिस तथा फिटनेस केंद्र के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए "आओ और खेलो" योजना को नियमित आधार पर जारी रखा है।
18. मंत्रि मंडलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) में विभिन्न अनुसूचीक और ख में 01 अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में छह (06) अध्यक्षों/सदस्यों की नियुक्तियों, स्वायत्त निकायों में तीन (03) मुख्य कार्यकारी निकायों की नियुक्तियों, मंत्री जी के लिए एक (01) वैयक्तिक सहायक की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव तथा मंत्री जी के लिए एक (01) विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव तथा एक (01) अधिकारी को मुख्य सर्तकता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को मंत्रि मंडलीय नियुक्ति समिति द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
19. फरवरी, 2017 के अन्त तक 1749 लोक प्राधिकरणों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सूचना कार ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ दिया गया है।